गुजरात में महिलाओं के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

786. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक गुजरात में महिलाओं के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा 1993–94 और 1994–95 के दौरान प्रस्तावित योजना के लिये जिले-वार कितनी-कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) किन-किन स्थानों पर इन संस्थानों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा): (क) से (ग) श्रम मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक सहायियत व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें केन्द्र सरकार तथा गुजरात सहित 28 राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन भाग ले रहे हैं । राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में परियोजना स्कीमें केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों के पैटर्न पर ही कार्यान्वित की जा रही हैं । राज्य/संघ शासित प्रदेश विश्व बैंक सहायियत नहीं हैं । केन्द्र सरकार ही विश्व बैंक से ऋण की राशि प्राप्त करती है । स्कीमों को कार्यान्वयन हेतु बजट राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । व्यय का 50% केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

परियोजना के अंतर्गत भावनगर, विसनगर, उत्तर संधा तथा बिल्लिमोरा स्थित चार नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं । गुजरात राज्य द्वारा वर्ष 1993–94 के दौरान 36.62 लाख रुपये तथा वर्ष 1994–95 के दौरान 37.97 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है ।

गुजरात में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

787. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पिछले 2 वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक क्रमश: कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गये हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और इनमें से पुरुषों और महिलाओं की अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ग) सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) गुजरात के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दिसम्बर, 1992, दिसम्बर, 1993 तथा सितम्बर, 1994 के अंत में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या
1992 . .	10,30,239
1993 . .	9,72,832
1994 (सितम्बर) .	9,17,270

(ख) वर्ष 1992, 1993 तथा 1994 (सितम्बर, 1994 तक) के दौरान गुजरात में विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया

गया उनमें पुरुषों तथा महिलाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार था :—

वर्ष	नियुक्तियां		
	पुरुष	महिला	कुल
1992	24,520	2,664	27,183
1993	26,523	2,737	29,260
1994 जनवरी-सितंबर	17,176	2,243	19,419

(ग) नियुक्ति गतिविधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा वार्षिक लक्ष्य नियत किया गया है । वर्ष 1994–95 के लिए 32000 नौकरियों का लक्ष्य नियत किया गया है ।

Directions of Regional Director (ESIC) Bangalore

788. SHRI GUNDAPPAKOR-WAR : Will .the Minister of Labour BOUR be pleased to state :

(a) whether Regional Director of Employees State Insurance Corporation (ESIC) of Bangalore region has directed the industries to be more responsible towards their employees with better compliance of ESI requirement ;

(b) if so, the main points of ESI requirements; and

(c) the extent to which industries have been asked to comply with them ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (c) The power using factories employing 10 or more persons and non power using factories/establishement employing 20 or more persons located in the notified areas are convera-ble under the ESI Act, 1948. The Regional Director, ESIC, Bangalore has requested the employers to comply with the provisions of the ESI Act by making timely payment of contributions, submission of Declaration Forms in respect of newly covered employees and returns about contribution etc. as prescribed under the Act/Scheme.

Proposal to amend the minimum wages Act and contract labour Act

789. SHRI V. RAJAN CHEL-LAPPA : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government propose to amend the Minimum Wages Act 1948 odd the contract Lebour Act Regulation and Abolition Act, 1970);

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government also propose to enact any new law to improve the socio-economic condi tions of the workers engaged in agriculture and construction work; and

(d) if so, by when a law is likely to be enacted ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) and (b) Yes, Sir. The proposals for amendment of the Minimum Wages Act, 1948 mainly relate to expeditious settlement of wage claims, enhancement of penalties for violation of the provisions of the Act etc. The proposals for amendment of the Contract Labour (Regulation and abolition) Act, 1970 mainly relate to streemlining of licensing procedures, provision of welfare facilities, enhamcement of penalties for